vii) ई–प्रशासन के घटक – जैसे ऑनलाइन व्यापार, निविदाएँ तथा ऑनलाइन खर्च–विवरण प्रणाली में नई जान डाल सकता है।

7.5 निष्कर्ष

यू एन आवास–III (2016) के अनुसार अधिकतर देशों में, शहरी प्रशासन प्रणालियाँ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं, तथा स्थायी शहरी निकाय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उनमें महत्वपूर्ण बदलाव लाने की आवश्यकता है।

चौहत्तरवें संविधान संशोधन में यह प्रावधान है कि स्वायत्त शाक्षी संस्थानों के रूप विकसित होने तथा लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम होने के लिए यह आवश्यक है कि उनकी शक्तियों का हस्तांतरण किया जाये। यद्यपि, इन निकायों के सामने कार्यों, कार्मिकों तथा वित्त से जुड़ी अनेक प्रकार की समस्याएँ हैं। इन निकायों की वर्तमान स्थिति तथा उनके कारणों का इस इकाई में वर्णन किया गया है। इन निकायों को और अधिक शक्तियाँ प्रदान करने की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। इसे पूरा करने के लिए सशक्त राजनैतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है।

7.6 शब्दावली

सहयोगिता का सिद्धांत : सरकारी सेवाएँ प्रदान करने का अधिकार सबसे निचले स्तर की सरकारों को दिया जाना, जिससे उनके उत्पादों तथा सेवाओं को प्रदान की क्षमता बढ़े।

हस्तांतरण : निचले स्तर पर सरकारों को शक्तियां हस्तांतरित करने की प्रक्रिया।

संरचनात्मक हस्तांतरण : अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र के कार्यबल को दूसरे क्षेत्र में हस्तांतरित करना – जैसे कृषि, विनिर्माण व सेवाएं।

7.7 संदर्भ

Ahluwalia, I.J., Mohanty, P.K.,Mathur, O.,Roy, D.,Khare, A. &Mangla, S. (2019). *State of Municipal Finances in India: A Study prepared for the Fifteenth Finance Commission*. New Delhi, India: ICRIER.

Chakraborty, P., Gupta, M.& Singh, R.K. (2018).*Overview of State Finance Commission Reports*. New Delhi, India: NIPFP.

Government of India.(1953-54). *Report of the Taxation Enquiry Commission*. New Delhi, India: Ministry of Health, Family Planning and Urban Development.

Government of India.(1964). *Report of the Rural Urban Relationship Committee.* New Delhi: Ministry of Health & Family Planning.

Government of India.(1968). *Report of the Committee on the Service Conditions of Municipal Employees*. New Delhi: Ministry of Finance.

High Powered Expert Committee.(2011). *Report on Indian Urban Infrastructure and Services.*
New Delhi, India: ICRIER.

ICF GHK (2014).*Approach towards Establishing Municipal Cadres in India*. New Delhi, India: MoUD and the World Bank.

ICRA.(2016). *Rating methodology for Urban Local Bodies*. New Delhi, India: ICRA.

Kamath, L & Zachariah, Y. (2015*). Impact of JNNURM and UIDSSMT/IHSDP Programmes on Infrastructure and Governance Outcomes in Cities/Towns in India: A Review of the State of Knowledge*. Working Paper- 7. Mumbai, India: TISS.

Mathur, O.P. (2011).*Municipal Finance Matters: India Municipal Finance Report*. New Delhi, India: NIPFP.

Mohan, L. (Jan 04, 2020).Only 12 Regular Executive Officers for 54 Municipal Councils.*The Tribune*. Chandigarh.

NIUA. (2015). *A Study to Qualitatively Assess the Capacity Building Needs of Urban Local Bodies (ULBs)*. New Delhi, India: NITI Aayog.

Pandey, K.K. (2012).*Administration of Urban Development and Urban Service Delivery, Theme Paper for the 56th Members' Annual Conference of IIPA*. New Delhi, India: IIPA.

Pandey, K.K. (25 December,2020). *Financial Express*.Bolster,ULB Capacity to Raise Revenue.

Rao, G.M.(2013).*Property Tax System in India: Problems and Prospects of Reform*.Working Paper No. 2013-14. New Delhi, India: NIPFP.

7.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) आपके उत्तर में निम्नलिखित शामिल होना चाहियेः

- कई एजेंसियों के कामकाज में
- इस प्रकार के हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिये एक राजनीतिक सहमति बनाने की आवश्यकता
- प्रत्येक कार्य के लिये पर्याप्त और सतत् संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये अभिनव दृष्टिकोण

- 18 कार्यों में से प्रत्येक से जुड़ी जटिलताओं के लिये आवश्यकताओं और चुनौतियों की जवाबदेही के लिये सक्षम जनशक्ति की आवश्यकता

2) आपके उत्तर में निम्नलिखित शामिल होना चाहियेः

- नगरपालिका प्रशासनिक सेना कार्यकारी, सामाजिक विकास तथा स्टाफ सेवाओं को नियंत्रित करती है।
- नगरपालिका तकनीकी सेवा – नगर वित्ति योजना, इंजीनियरिंग, परिवहन तथा ई–प्रशासन सेवाओं का नियंत्रण करती है।
- नगरपालिका वित्तीय सेवा – खातों के रखरखाव, राजस्व एवं वित्तीय तथा लेखा–परीक्षण सेवाओं का नियंत्रण करती है।

बोध प्रश्न 2

1) आपके उत्तर में निम्नलिखित शामिल होना चाहियेः

- भूमियों तथा भवनों पर कर लगाए जाएँ।
- कर अथवा चुंगी (चुंगी सभी राज्यों में समाप्त कर दी गई, मुम्बई में ईंधन तथा यातायात क्षमता के आधार पर बनी रही)।
- वाहन कर – इंजन वाले वाहनों पर कर।
- पशु एवं नौका कर।

- व्यवसायों, व्यापारों, आजीविकाओं तथा रोजगार पर कर।
- विज्ञापनों – जो समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं होते, पर कर।
- अभिनय केन्द्रों तथा नाटक घरों पर कर।
- अचल संपत्ति के बिक्री या हस्तांतरण पर कर (स्टेंप ड्यूटी आदि)।
- उत्पादों तथा व्यक्तियों के सड़क अथवा जल के रास्ते ले जाए जाने पर कर।

2) आपके उत्तर में निम्नलिखित शामिल होना चाहियेः

- कर राजस्व में संपत्ति कर, व्यवसाय कर, मनोरंजन कर, विज्ञापन कर आदि शामिल हैं।
- अधिकांश स्थानीय निकायों के लिये संपत्ति कर आय का प्रमुख स्रोत बना हुआ है।
- नगर निगम की संपत्तियों से किराया, पानी और स्वच्छता के लिये उपयोगकर्ता शुल्क आदि शहरी स्थानीय स्वशासन प्रणाली के लिये गैर–कर प्राप्तियों के प्रमुख स्रोत हैं।